ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी)

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** आर्थिक मुद्दे

प्रसंग

- हाल ही में, शीर्ष इंटरनेट कंपनियों और तकनीकी प्लेटफार्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली उद्योग संस्था इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने नियामक अनिश्चितता के दृष्टिगत चार वर्ष पहले शुरू हुई ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) को भंग करने का निर्णय लिया है।
- विदित है कि बीएसीसी ने एक दर्जन से अधिक क्रिप्टो और ब्लॉकचैन कंपनियों के लिए सरकार के साथ संपर्क करने के लिए एक छत्र इकाई के रूप में काम किया।

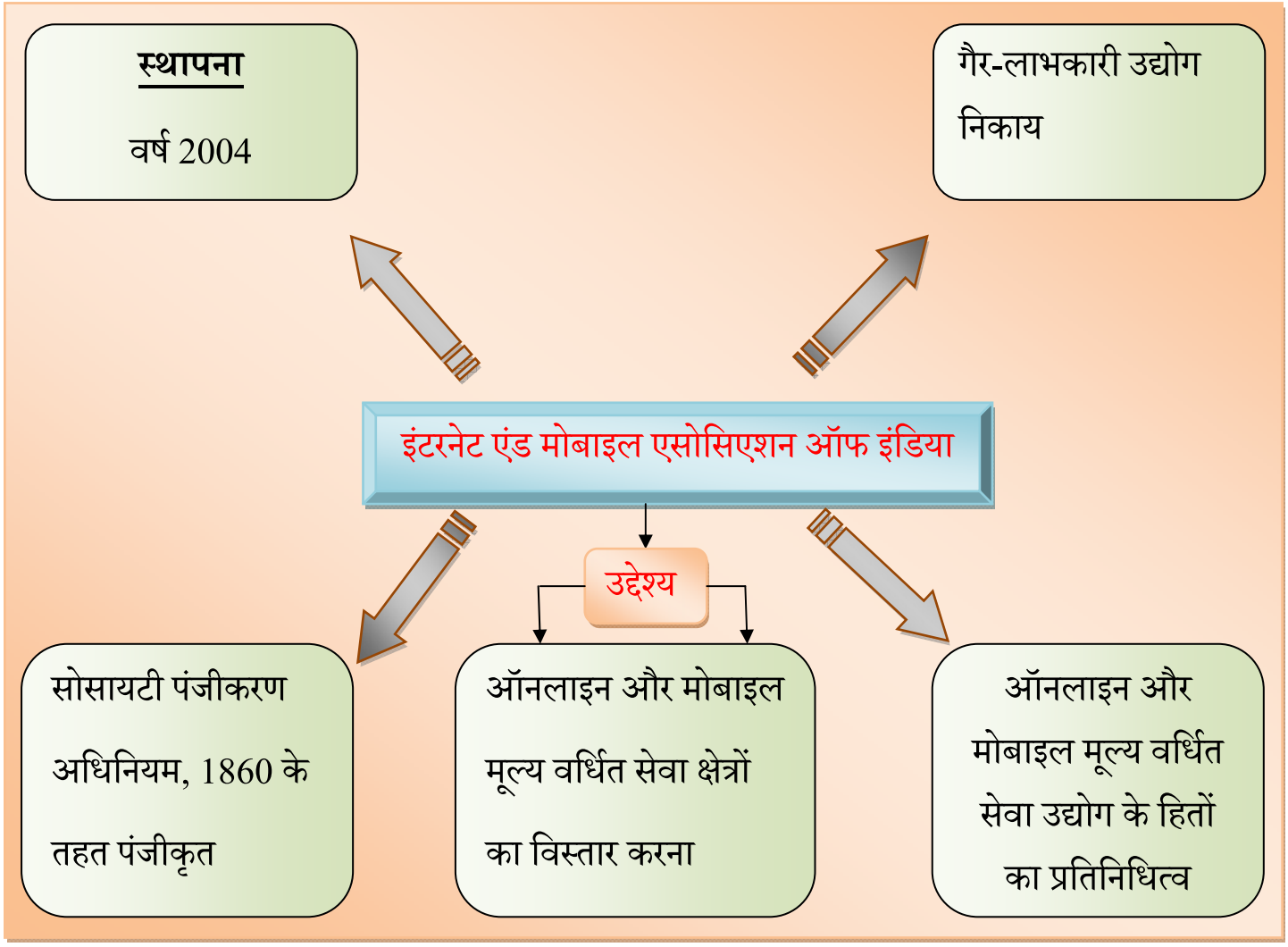

प्रभाव

- ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (Blockchain And Crypto Assets Council) को बंद करने के बाद भी संस्थान ब्लॉकचेन सेगमेंट में अपना योगदान देगा।
- साथ ही, संस्थान देश की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को भी प्रोत्साहन देने में सहायता करती रहेगी

ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC)

- बीएसीसी एक उद्योग संघ है, जो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में था।
- यह भारत में क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह सरकार के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न ब्लॉकचेन फर्मों के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय क्रिप्टो उद्योग के विभिन्न पक्षों जैसे कि CoinSwitch Kuber, WazirX, CoinDCX, Zebpay, BitBNS, Vauld, Chingari, Mudrex आदि का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे नियामक निकायों के लिए क्रिप्टो उद्योग के तर्कों को समर्थन प्रदान करता है।
- विदित है कि इसने सभी क्रिप्टो प्लेटफार्मों के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत की थी, जिसको अद्यतन किए जाने की संभावना थी।

निर्णय से उत्पन्न मुद्दे

- इस निर्णय से भारत के क्रिप्टो उद्योग के प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जो सख्त करों, भुगतान प्रोसेसर के एक्सचेंजों पर प्रभाव, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रैश और वैश्विक बियर बाजार प्रभावित हो सकता है।
- एसोसिएशन अन्य उभरते डिजिटल क्षेत्रों के लिए अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, जो डिजिटल भारत में अधिक तत्काल और प्रत्यक्ष योगदान देता है।

- यह विशेष रूप से वित्तीय समावेशन और सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को बढ़ावा देने पर बल देगा।
- आरबीआई का मानना है कि निजी क्रिप्टोकरेंसी से देश की मौद्रिक स्थिरता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है।
- सरकार द्वारा क्रिप्टो क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के लिए मानदंडों को कड़ा करने और आरबीआई द्वारा उठाए गए रुख को देखते हुए बीएसीसी को खत्म करने का प्रस्ताव कुछ समय से आईएएमएआई में विचाराधीन था।

डिजिटल रुपया

- विदित है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2022 के भाषण में जिन प्रमुख व्यक्तिगत वित्त घोषणाओं की, उनमें से एक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करने के बारे में थी।
- डिजिटल रुपया एक केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

- सीबीडीसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है।
- सीबीडीसी किसी देश की आधिकारिक मुद्रा का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन है, जो विनिमय के माध्यम, खाते की इकाई, मूल्य के भंडार और आस्थगित भुगतान के मानक के रूप में बुनियादी कार्यों को पूरा करता है।
- सरल शब्दों में व्याख्या की जाये तो सीबीडीसी किसी देश का लीगल टेंडर है, क्योंकि इसे सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाता है। यह किसी देश के मॉनिटरी अथॉरिटी द्वारा जारी ऑफिशियल करेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन है।

सर्वेक्षण

- बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 86 प्रतिशत केंद्रीय बैंक सीबीडीसी को अपनाने की तैयारी में हैं। वहीं, लगभग 15 प्रतिशत देश इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं।

- सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक करेंसी ही है, लेकिन यह कागज (या पॉलीमर) नहीं है। यह भारत की फिएट करेंसी- भारतीय राष्ट्रीय रुपया (INR) जैसी होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज (विनिमय) किया जा सकेगा।
- आरबीआई के अनुसार, यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में सॉवरेन करेंसी है और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी (चलन में मुद्रा) के रूप में होगी।

सीबीडीसी की आवश्यकता

- सीबीडीसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (DLT) द्वारा समर्थित होगा, लेकिन यह एक लाइसेंस प्राप्त ब्लॉकचेन होगा, जो इसे ऐसे क्रिप्टो एसेट्स से भिन्न करेगा, जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है।
- सेंट्रल मॉनीटरी अथॉरिटी के पास ब्लॉकचेन का नियंत्रण होगा।
- ज्ञातव्य है कि कागजी मुद्रा के उपयोग में लगातार कमी आ रही है और आरबीआई इसके इलेक्ट्रॉनिक रूप को और अधिक लोकप्रिय बनाना चाहता है।
- डिजिटल मुद्रा अधिक प्रभावी होगी और प्राइवेट करेंसी के खतरे और होने वाले नुकसान से बचने में मदद करेगी।
- डिजिटल करेंसी को जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक बार जारी किए जाने के बाद इसका अस्तित्व बना रहेगा।

सीबीडीसी के लाभ

- यह बिना किसी अंतर-बैंक निपटान के वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा ।
- सीबीडीसी को अपनाने वाले देशों के बीच विदेशी व्यापार लेन-देन में तेजी लाई जा सकती है।
- बड़े पैमाने पर नकदी के उपयोग को सीबीडीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है ।
- कागजी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।
- वे भुगतान प्रणालियों के एक सस्ता और अधिक वास्तविक समय के वैश्वीकरण को सक्षम कर सकते हैं।

- एक भारतीय निर्यातक के लिए बिना किसी मध्यस्थ के वास्तविक समय के आधार पर भुगतान करना संभव है।
- सीबीडीसी को अपनाने से बैंकिंग प्रणाली पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- भारत पहले से ही डिजिटल भुगतान में अग्रणी है, किन्तु छोटे मूल्य के लेन-देन के लिए नकदी की प्रभाविता बनी हुई है।
- फरवरी 2020 में आरबीआई बुलेटिन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा किए गए केंद्रीय बैंकों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 66 प्रतिक्रिया देने वाले केंद्रीय बैंकों में से लगभग 80 प्रतिशत केंद्रीय बैंकों ने किसी न किसी रूप में सीबीडीसी के उपयोग का पता लगाने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं।
- ये केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में सीबीडीसी के संभावित लाभों और प्रभावों पर विचार कर रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं।
- वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढांचे में बदलाव के साथ सीबीडीसी की शुरुआत की सिफारिश की थी, जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने को विनियमित करने का अधिकार देता है।

अन्य देशों में स्थिति

- भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीबीडीसी या डिजिटल रुपये को लॉन्च किए जाने की संभावना है।
- इसे दो रूपों- रिटेल डिजिटल रुपी (Retail Digital Rupee) और होलसेल डिजिटल रुपी (Wholesale Digital Rupee) में लॉन्च करने की योजना है।
- वहीं वैश्विक अध्ययन पर नाइजीरिया नायरा (Naira) नाम की अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
- वेनेजुएला डिजिटल बोलीवियर (Bolivar) लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
- साउथ कोरिया डिजिटल युआन का पायलट परीक्षण कर रहा है।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी), अमेरिका, रूस, चीन और तुर्की भी सीबीडीसी को लेकर अपनी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस